



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 909 राँची, शुक्रवार, 3 अग्रहायण, 1939 (श०)  
24 नवम्बर, 2017 (ई०)

---

#### खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

-----  
संकल्प

3 अक्टूबर, 2017

**विषय:-** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (DBT) लागू करने की प्रक्रियाओं का निर्धारण एवं स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या - खा.प्र. 01/ज.वि.प्र.कं./10-02/2016 - 4145, -- राज्य में माह अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है । वर्तमान में इस अधिनियम के अन्तर्गत 56,34,536 परिवार के कुल 2,59,47,802 लाभुक आच्छादित हैं जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 79 प्रतिशत है । उल्लेखनीय है कि अधिनियम के अन्तर्गत राज्य की 86.48 प्रतिशत ग्रामीण आबादी एवं 60.20 प्रतिशत शहरी आबादी को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है । इस संदर्भ में अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 2,64,43,330 निर्धारित की गई है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 80.16 प्रतिशत है ।

2. उक्त परिपेक्ष्य में वर्तमान में अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों में से 8,97,500 परिवार (37,66,412 लाभुक) अन्त्योदय की श्रेणी में हैं जिन्हें 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से वितरित किया जा रहा है। शेष 47,37,036 परिवार (2,21,81,390 लाभुक) पूर्वविकता प्राप्त गृहस्थ परिवार की श्रेणी में हैं जिन्हें 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह की दर से वितरित किया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली में सुधार हेतु कई आवश्यक कदम उठाये जाने की बात कही गयी है। इनमें से एक बिन्दु नगद हस्तांतरण, फूड कूपन या अन्य योजना के क्रियान्वयन का उल्लेख है। उक्त परिपेक्ष्य में अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (DBT) प्रारम्भ किया जाना एक अच्छा विकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न का गैर वाँछित उपयोग पर रोक लगाना तथा पात्र लाभुकों को ही अनुदान का लाभ पहुँचाना है।

4. खाद्यान्न वितरण योजनान्तर्गत “पहल” की तर्ज पर अनुदान की राशि में DBT लागू किये जाने हेतु राँची जिलान्तर्गत नगड़ी प्रखण्ड को पायलट आधार पर चयन किया गया है। योजना की सफलता के उपरान्त इसे सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जायेगा।

5. उल्लेखनीय है कि राज्य में किरासन तेल वितरण योजनान्तर्गत DBT लागू कर दी गई है। इस हेतु लाभुकों के डाटाबेस का पूर्ण अंकीकरण किया जा चुका है। इस संदर्भ में राँची जिलान्तर्गत नगड़ी प्रखण्ड में लाभुकों के राशन कार्ड के साथ आधार सिडिंग एवं बैंक खाता की सिडिंग लगभग पूरी कर ली गयी है।

6. खाद्यान्न वितरण योजनान्तर्गत जहाँ तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) लागू किये जाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में विभागीय अधिसूचना संख्या 2529, दिनांक 27 जून, 2016 के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड को राज्य अभिकरण के रूप में चिन्हित किया गया है जिसे भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से नकद सहायिकी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य में खाद्यान्न वितरण योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) लागू करने हेतु विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 2528, दिनांक 27 जून, 2016 के माध्यम से निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जा चुका है।

7. योजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया:-

- (i) योजना के लागू होने पर लाभुक द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार से गैर अनुदानित दर पर खाद्यान्न का क्रय किये जाने एवं भारत सरकार तथा राज्य

सरकार द्वारा खाद्यान्न पर दी जाने वाली अनुदान की राशि संबंधित लाभुक के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित किया जायेगा ।

- (ii) भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दी जानेवाले अनुदान की राशि राज्य स्तर पर चयनित अभिकरण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के खाता में उपलब्ध करायी जायेगी । तत्पश्चात् अनुदान की राशि जिला स्थित जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जायेगा । जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा संबंधित अनुदान की राशि सीधे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा ।
- (iii) योजना के आरम्भ में एक माह के अनुदान की राशि अग्रिम के तौर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जायेगा । तत्पश्चात् आगामी माहों में लाभुक द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न की मात्रा पर देय अनुदान की राशि स्थानांतरित किया जायेगा । यदि लाभुक आवंटित माह का खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में उपलब्ध कराये गये अग्रिम राशि से अगले माह तक खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। लाभुकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (DBT) अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त कर लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा ।

इसके बावजूद यदि लाभुक द्वारा खाद्यान्न नहीं प्राप्त किया जाता है तो लाभुकों को बतौर अग्रिम उपलब्ध करायी गयी अनुदान की राशि की वसूली हेतु लोक माँग वसूली अधिनियम (Public Demand Recovery Act) के तहत कार्रवाई किया जायेगा ।

- (iv) योजना के प्रारम्भ में प्रथम दो माह में जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त किया जायेगा एवं बाजार दर पर खाद्यान्न वितरित किया जायेगा ।
- (v) जिस माह से DBT लागू किया जाना है उसके पूर्ववर्ती माह की 25वीं तारीख तक अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में बतौर अग्रिम के रूप में जमा किया जायेगा, ताकि माह की पहली तारीख से लाभुक जन वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सके ।
- (vi) खाद्यान्न पर अनुदान की राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जायेगा ।

- (vii) योजना की सफलता की समीक्षा के उपरान्त विभाग द्वारा इसे अन्य जिलों में लागू किया जायेगा ।
  - (viii) योजना का प्रचार प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य प्रसार माध्यमों से किया जायेगा ।
  - (ix) योजना लागू करने की विहित रीति का निर्धारण खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा भारत सरकार से प्राप्त निदेशों के आलोक में किया जायेगा ।
8. राज्य कोष से व्यय:- योजना के कार्यान्वयन में राजकोष पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा ।
9. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न पर उपभोक्ताओं को सीधे नगद अनुदान हस्तांतरण योजना लागू किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**विनय कुमार चौबे,**  
सरकार के सचिव ।

-----